इन्दौर में 24 जनवरी 2017 को आयोजित डिजिधन मेला के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी का भाषण

1. व्यापार–व्यवहार में डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग के तत्वावधान में आयोजित इस व्यापार मेले में आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्रिकेटर नमन ओझा एवं कत्थक नृत्यांगना रागिनी मक्खर भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबके समर्थन से डिजिटल लेन–देन करने में लोग ज्यादा प्रेरित होंगे। हमारा देश एक युवा देश है, तकनीकी रूप से सक्षम है। ऐसी योजनाओं से डिजिटल व्यवहार को अपनाने में लोग आगे आएंगे। डिजिटल और कैशलेस लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल से शुरूआत करके विभिन्न भागों में डिजि धन मेलों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। पूरे देश में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आयोजकों और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े सभी लोगों को उनकी सराहनीय पहलों के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूं।

2. डिजिटल लेन–देन को प्रोत्साहन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में दो नए स्कीम का ऐलान किया था। रिटेल ग्राहकों के लिए ''लक्की ग्राहक योजना'' और छोटे व्यापारियों के लिए ''डिजि धन व्यापार योजना''। इन योजनाओं के विजेताओं के नाम लकी ड्रॉ के आधार पर तय होंगे। उपहार के तौर पर कम से कम 1,000/– रुपये दिए जाएंगे। लक्की ग्राहक योजना के विजेता के नाम दैनिक और साप्ताहिक आधार पर चुने जाएंगे। डिजि धन व्यापार योजना के विजेता व्यापारियों के नाम का ऐलान हर हफ्ते होगा। यह स्कीम 14 अप्रैल तक चलेगी।

3. इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों एवं व्यापारियों को डिजिटल लेन–देन के लिए प्रोत्साहित करना है। मेले में बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए पी.ओ.एस. मशीनों के उपयोग, उसके registration एवं उसको मोबाइल नं. से लिंक करने के बारे में समुचित जानकारियां दी जाएंगी। मेले में डिजिटल डाकिया अभियान के माध्यम से आम जनता को प्रशिक्षित व जागरूक किया जाएगा। डिजिधन मेला में जिला पंचायतों को भी

कैशलेश ट्रांजेक्शन के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष यहां मौजूद हैं, उनसे भी आग्रह है कि वे अपने स्तर से भी इसको लोकप्रिय बनाएं।

4. सर्वप्रथम, लक्की ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार योजना का फायदा उठाने के लिए आपको यूपीआई (यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस), रूपे, एईपीएस (आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) और यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस डेटा) प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल पेमेंट करना होगा। अन्य प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले यूज़र लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार योजना का हिस्सा नहीं होंगे। छोटे एवं मझोले ग्राहकों को डिजिटल लेन–देन की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से ही इस योजना की शुरूआत की गई है।

5. केन्द्र सरकार के Financial Inclusion Fund, जिसपर लगभग 340 करोड़ रुपये का खर्च संभावित है, से इस योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नीति आयोग इस स्कीम के अंतर्गत गतिविधियों को चलाने, प्रचार–प्रसार करने एवं संबंधित विभागों से समन्वयन का कार्य करने एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्था है। जबकि नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया इससे संबंधित तकनीकी पहलुओं को देखेगी एवं सभी आंकड़ों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उन पर है।

6. इस योजना के तहत दिनांक 20 जनवरी 2017 तक 3,81,687 ग्राहकों एवं 21,000 व्यापारियों को cashless transaction के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। मुझे खुशी है कि लगभग 1 करोड़ 97 लाख लोग अब लेन–देन की इस प्रक्रिया को अपनाने लगे हैं। यह जानकर सुखद अनुभव होता है कि भारत के गांवों जैसे महाराष्ट्र में थाणे जिले का धसाई गांव, तेलंगाना का इब्राहिमपुर जैसे कई गांव अब पूरी तरह से कैशलेस हो चुके हैं और कई गांव तेजी से अर्थव्यवस्था के इस नए फार्मेट को अपनाने की ओर बढ़ चुके हैं। हाल ही मे सरकार ने डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और ईंधन की खरीद, राजमार्ग पथकर, रेल टिकट आदि पर छूट जैसी कई रियायतें दी हैं।

7. आज, संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों को मानवीय गतिविधियों के बहुत से क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा रहा है जिसमें व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सतत विकास और पर्यावरण शामिल हैं। एक राष्ट्र के रूप में प्रौद्योगिकियों के लाभों का उपयोग करते हुए हमें आर्थिक विकास में आगे रहना है। यह गर्व का विषय है कि अब भारत ऐसे अग्रणी देशों में शामिल है जिन्होंने तकनीकी उन्नति में असाधारण प्रगति की है, जिससे E-governance (ई–शासन) हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुए हैं। सूचना तकनीक का उपयोग कर लोक सेवाओं के समस्त तंत्र को बदलने के लिए हमारी सरकार ने भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की दृष्टि से ''डिजिटल इंडिया कार्यक्रम'' की शुरूआत की है।

8. चुनौतियों के बावजूद भारत सरकार ने देश के आर्थिक परिदृश्य को परिवर्तित करने के लिए सराहनीय पहल की हैं। जन–धन खातों को खोलने के संदर्भ में वित्तीय समावेशन हेतु एक बड़ा अभियान चलाया गया था। जिसमें अभी तक 25 करोड़ खाते खोले गए हैं। आधार को आधार प्रदान करते हुए; Direct Benefit Transfer का प्रायोगिक कार्यान्वयन किया गया है। जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एलपीजी वितरण और मनरेगा में लगभग 27,000 करोड़ रुपये बचाए गए हैं।

9. डिजिटल लेन–देन से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होने वाला है। Demonetization से बैंकों में जमा हुए पैसों से आम जन को सुविधाएं मिलेंगी। हमारे देश में 130 करोड़ नागरिकों में से 90 करोड़ लोगों के पास कोई न कोई बैंक खाता है। 108 करोड़ आधार कार्ड धारक हैं एवं 90 करोड़ मोबाइल प्रयोक्ता हैं। साथ ही रूपे कार्ड धारकों की संख्या भी 31 करोड़ है। हमारे देश में अब तक कुल 5 प्रतिशत लेन–देन कैशलेस होते थे और नकदी में व्यवहार 95 प्रतिशत था। अब डिजिटल प्रक्रिया के अपनाने से इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में टैक्स के नेट में लगभग 1 प्रतिशत लोग आते हैं। यदि इसका दायरा 5 प्रतिशत भी बढ़े, तो ऐसा अनुमानित है कि लगभग 85,000 करोड़ रुपये के राजस्व में वृद्धि होगी। इस धन का प्रयोग राष्ट्र के निर्माण एवं समाज के कल्याण हेतु किया जा सकता है। इस तरह से यह एक बहुत उपयोगी योजना है।

10. जन धन बैंक खाता खोले जाने, आधार कार्ड को मान्यता प्रदान करने एवं विभिन्न पायलट परियोजनाओं में Direct Benefit Transfer से सरकार ने सरकारी धन के अपव्यय को रोकने की पहल की है। काला धन का पता लगाने एवं कर चोरी रोकने से छिपा राजस्व निकलकर सामने आया है। नकद लेन–देन में मुद्रा के जाली होने के खतरे से भी यह लेन–देन बचाता है। अतः, न केवल यह लेन–देन सुरक्षित है बल्कि देशहित में है।

11. मैं यहां उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करती हूं कि आप आगे आएं और बदलते दौर की इस नई तकनीक का लाभ खुद भी उठाएं एवं दूसरों को डिजिटल लेन–देन करने के लिए निरंतर प्रेरित करें। आशा है, शीघ्र ही, समस्त भारत में यह लेन–देन पूर्ण रूप से लोकप्रिय हो जाएगा और अर्थव्यवस्था से fund leak, counterfeit note एवं terror funding जैसे खतरे खत्म हो जाएंगे।

12. मैं समाज के विभिन्न वर्गों के शिक्षित और तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से आग्रह करती हूँ कि वे उन लोगों की सहायता करें जिन्हें तकनीकी या डिजिटल प्रणाली की उतनी जानकारी नहीं है। अतः बैंकों, पंचायतों, नगर निकायों, स्कूलों और कालेजों सहित हम सबकी यह ज़िम्मेदारी हैं कि हम सब एक साथ आगे आयें और जनता के लाभार्थ जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाएं।

धन्यवाद।